

किसानों ने पंजाब में 3 घंटे रेलवे ट्रैक जाम किए

● चंडीगढ़ में एसकेएम की इमरजेंसी मीटिंग, डल्लेवाल को समर्थन पर फैसला

लुधियाना/जालंधर/मोहाली (एजेंसी)। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज किसानों ने पंजाब में 3 घंटे रेलवे ट्रैक जाम किए। किसान दोपहर 12 बजे 48 जगहों पर ट्रैक पर बैठ गए। 3 बजते ही किसानों ने ट्रैक खाली कर दिए। रेलवे ट्रैक जाम होने से दिल्ली-पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लुधियाना के डंडारी कलां में रोकना पड़ा। कुछ ट्रेनों को कैसिल तो कुछ को डायवर्ट भी करना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन से करीब 60 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा।

● अंशान कर रहे डल्लेवाल पर कहा- वे जननेता, उनका स्वस्थ रहना जरूरी, तुरंत इलाज कराएं

पटियाला (एजेंसी)। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगें लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा, डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अश्विन ने अचानक लिया संन्यास

सीरीज बीच में छोड़कर लौटेंगे घर

ब्रिस्बेन (एजेंसी)। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और वहां इसकी घोषणा की। संन्यास से पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए थे। इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था। अश्विन एडिलेड डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुके अश्विन- 38 साल का यह स्पिनर भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुका है। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में सातवें स्थान पर हैं। अश्विन के नाम 106 टेस्ट में 537 विकेट हैं। 59 टेस्ट दैकर सात विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है।

गेटवे ऑफ इंडिया के पास फेरी बोट पलटी, 13 की मौत

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक फेरी बोट के पलटने की घटना सामने आई है। यह बोट ट्रिस्ट को एलीफंटा ले जा रही थी। तभी इस नाव का संतुलन बिगड़ गया। वीडियो में काफी लोगों के सवार होने की पुष्टि हुई है। मुंबई पुलिस और भारतीय नौसेना बचाव अभियान चला रही है। अभी तक 13 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है। नाव में कुल 56 यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सभी एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है। फेरी बोट हादसे में अभी तक 21 लोगों को बचा लिया गया है। प्रशासन ने एक मौत की पुष्टि की है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू किए गए लोगों को उपचार के लिए भेजा गया है। काफी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि नाव एलीफंटा जा रही थी।

वन नेशन-वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका का नाम कांग्रेस ने 3 और सांसदों को नॉमिनेट किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक देश, एक चुनाव के लिए संसद में मंगलवार को पेश हुए 129वां संविधान (संशोधन) बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी (जेपीसी) में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस ने जेपीसी के लिए चार सांसदों के नाम नॉमिनेट किए हैं। इनमें प्रियंका के अलावा मनीष तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुखदेव भगत सिंह शामिल हैं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है।

अंबेडकर-अडाणी-मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन

यूपी में यूथ कांग्रेस महासचिव की मौत

राजस्थान में गहलोत-पायलट एक मंच पर आए, बिहार में पुलिस ने पैदल मार्च रोका

नई दिल्ली/जयपुर/पटना (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान, अडाणी मुद्दे और मणिपुर हिंसा को लेकर आज देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी सभी राज्यों के राजभवन तक मार्च निकाल रही है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। बिहार के पटना में कांग्रेस के राजभवन मार्च को पुलिस ने रोक दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान यूपी में यूथ कांग्रेस महासचिव की मौत हो गई। हैदराबाद में कांग्रेस ने नेकलेस रोड स्मारक से राजभवन तक ‘चलो राज भवन’ रैली निकाली- तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस ने नेकलेस रोड स्मारक से राजभवन तक ‘चलो राज भवन’ रैली निकाली। जम्मू में जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद और हैदराबाद में रेंवत रेड्डी के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। असम के गुवाहटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन- असम के गुवाहटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की। पटना में राजभवन मार्च को प्रशासन ने रोक दिया बिहार के पटना में कांग्रेस पार्टी के राजभवन मार्च को प्रशासन ने रोक दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का-मुक्का भी की। मार्च रोकने के बाद विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कारोबारी गौतम अडाणी की गिरफ्तारी की मांग और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। राजस्थान – कांग्रेस ने पैदल मार्च कर राजभवन का घेराव किया – राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च कर राजभवन का घेराव किया जाएगा। सचिन पायलट ने कहा कि कौन नेता आया, नहीं आया। इधर-उधर की बातें छोड़ो। सब एक हैं। एक साथ लड़ेंगे और चार साल बाद सरकार लेकर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकराम जुली ने कहा- अंबेडकर का नाम लेना फैशन है तो हम यह फैशन करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डेटासरा ने कहा कि विपक्ष लंबे समय से अडाणी मामले में जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है।

नदियों के संगम से मध्य प्रदेश-राजस्थान को मिलेगा जल-शक्ति का सदा-उर्वरा आशीष : मुख्यमंत्री

संनोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ‘लाइला’ कहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पेयजल भी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पीकेसी परियोजना दोनों राज्यों की नदियों को सदानोरा बनाए रखेगी, इससे इन नदियों से संबद्ध भूमि शस्य-श्यामला बनेगी। पीकेसी परियोजना से मध्य प्रदेश को 3,000 और राजस्थान को 4,103 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों

संनोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ‘लाइला’ कहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पेयजल भी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पीकेसी परियोजना दोनों राज्यों की नदियों को सदानोरा बनाए रखेगी, इससे इन नदियों से संबद्ध भूमि शस्य-श्यामला बनेगी। पीकेसी परियोजना से मध्य प्रदेश को 3,000 और राजस्थान को 4,103 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों

संनोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को छतरपुर जिले के स्टार्टेड स्टेडियम प्रांगण में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि 11 से 26 दिसम्बर तक जन-कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 1 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 3 बजे पन्ना के पॉलिटेक्निक ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पन्ना में जल-कलश यात्रा, संत सम्मेलन और लोक कल्याण शिविर होंगे।

पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री, राजस्थान के करौली में 1.3 डिग्री

● कश्मीर में झरना जमा, देश के 35 सबसे ठंड़े शहरों में 10 मध्य प्रदेश के

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर/ श्रीनगर (एजेंसी)। देश के 8 राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहां 4-5 दिन तक सदी और शीतलहर जारी रहेगी। उधर, पंजाब में भी ठंड का काफी असर है। फरीदकोट में पहली बार रात का पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। अबोहर में पारा 0.9 डिग्री रहा। पंजाब के दिन के औसत तापमान में आधा डिग्री की गिरावट आई है। जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। बारामूला जिले के तंमर्ग में 30 मीटर ऊंचा द्रग झरना ठंड के चलते जम गया है। कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग जैसे देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के भी 10 शहर शामिल हैं। पंचमढ़ी 11वें स्थान पर है। यहां तापमान 1.6 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। यहां लगातार चौथे दिन शीतलहर चली, जो एक नया रिकॉर्ड है। दिसंबर में इससे पहले लगातार 4 दिन शीतलहर कभी नहीं चली है।

भतीजा बना ‘राक्षस’, बुआ को बना दिया ‘सूर्यनखा’

राजस्थान में जमीन का मसला

जालोर (एजेंसी)। भारत में नाक काटने का जिह्वा आते ही रामायण काल की सूर्यनखा का विवरण किया जाता है। लेकिन राजस्थान के जालोर जिले में जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपनी बुआ की नाक काट देने का हैरान करने वाला कृत्य कर दिया है। उसने अपनी बुआ की चाकू से नाक काट कर अलग कर दिया। इस दौरान चाकू के हमले से पीड़िता बुरी तरह लहलुहान हो गई, जिसे बाद में उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर, मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हैरान कर देने वाला यह मामला जालोर के सायला थाना क्षेत्र का है, जहां मोकणी गांव में पीड़ित बुआ और भतीजे के बीच जमीनी विवाद सामने आया। जानकारी के अनुसार पीड़ित बुआ कुकी देवी जमीन के मामले को लेकर मोकणी गांव में अपने भाई के पास गईं। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला के प्लाट पर भतीजे ओमप्रकाश ने कब्जा कर रखा था।

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को कुवैत की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह 43 वर्षों में इस खाड़ी देश की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत और कुवैत के बीच ‘बहुआयामी’ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। मोदी, कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह के निमंत्रण पर यह यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान मोदी कुवैत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय का बयान –विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक समय से पारंपरिक रूप से घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।” इससे पहले, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। भारत, कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “यह यात्रा भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।

कुवैत भारत का छठा कच्चा तेल सप्लायर

कुवैत, भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमरीकी डॉलर रहा। कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है। अमीर शेख सबाह अल अहमद अल जाबर अल सबाह जुलाई 2017 में निजी यात्रा पर भारत आए थे। इससे पहले 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री ने भारत की उच्च स्तरीय यात्रा की थी।

संपादकीय

उम्मीद से भरा त्रिपक्षीय करार

महत्वाकांक्षी ‘पार्वती- कालीसिंध- चंबल नदी जोड़ो परियोजना’ पर जयपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में त्रिपक्षीय अनुबध्द पर हस्ताक्षर होना मप्र और खासकर मालवा चंबल क्षेत्र के विकास की दृष्टि से स्वागतये कदम है। यह अनुबंध मप्र और राजस्थान राज्यों के बीच हुआ है, जहां दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती चाहिए कि इस परियोजना पर तेजी से काम होगा और जल्द से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह परियोजना ग्वालियर चंबल व मालवा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है। इस समूची परियोजना पर 72 हजार करोड़ रू. की लागत आएगी और इससे मप्र के 11 जिलों के 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 40 लाख से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के मालवा और चंबल के क्षेत्र के लाखों किसान इस परियोजना के माध्यम से लाभ ले सकेंगे। परियोजना का भूमिपूजन राजस्थान के टोंक खुर्द कृषि मंडी परिसर में सम्पन्न हुआ। इस परियोजना से गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना के 2094 गांव लाभान्वित होंगे। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 21 बांध एवं बैराज बनाए जाएंगे। मप्र में लगभग 36 हजार 800 करोड़ रुपए से कार्य करवाए जाएंगे। इस परियोजना के बारे में मप्र के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिसावट ने बताया, एमपी में 35 हजार करोड़ रुपए और राजस्थान में 37 हजार करोड़ के काम होंगे। 90 फीसदी राशि केंद्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इसमें शक नहीं कि मप्र में भाजपा के 20 साल के शासन काल में सिंचाई क्षमता के विकास और विस्तार पर काफी ध्यान दिया गया है। आज राज्य में सिंचित कृषि क्षेत्र 169.48 लाख हेक्टेयर तक जा पहुंचा है। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना इस में और वृद्धि करेगी। यही कारण है कि आज मप्र देश के पांच अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल हो गया है। कुछ फसलों के उत्पादन में तो हम देश में नंबर वन हो चुके हैं। लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ सरकार और प्रदेश के समक्ष कई नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। जिस तेजी से राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ा है, उस तेजी से न तो फसलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है और न ही भंडारण व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़े हैं। मप्र का कच्चा माल राज्य में ही प्रोसेस हो, इस बारे में बहुत कम प्रगति हो सकी है। बेहतर भावों के लिए किसानों को अभी भी या तो दूसरे राज्यों का रूख करना पड़ता है या फिर अपने पौने दामों पर फसल बेचकर घाटा उठकर खेती करने पड़ती है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और खुद को किसान का बेटा कहने वाले मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान माना था कि कृषि उत्पादन वृद्धि के मामले में हमारे किसानों ने जो कमाल किया है, उस तुलना में उपज के भंडारण और प्रसंस्करण के मामले में हम अभी नहीं खूद सके हैं। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना इसमें कितनी मददगार होती है, यह देखने की बात है। औद्योगिकरण के मामले में मप्र पड़ोसी राज्यों की तुलना में अभी भी पीछे है। लिहाजा हमे कृषि पर ही और ज्यादा ध्यान देना होगा। मप्र में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र अभी भी यही है। ऐसे में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक जैसी परियोजनाओं की हमे और आवश्यकता है। लेकिन पर्यावरण बचाने का भी ध्यान रखना होगा। इसी तरह केन बेतवा परियोजना भी तेजी से आगे बढ़ने की राह देख रही है।

नजरिया

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, कालीसिंध और चंबल का पानी एक बड़े जलस्रोत के रूप में बहता है। मध्यप्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरूआत के बाद अब उपरोक्त नदियों को जोड़े जाने की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में रख दी है। इसके प्रतीक स्वरूप तीनों नदियों के पानी को एक घड़े में भरा गया। तत्पश्चात भारत सरकार और राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 72000 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च होंगे। इसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी। इस राशि में से 35000 करोड़ रुपए मध्यप्रदेश और 37000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार खर्च करेगी। इसमें मध्यप्रदेश के 13 जिलों के 3217 ग्रामों की सूरत बदल जाएगी। दोनों प्रदेशों में मिलाकर 27 नए बांध बनेंगे और 4 पुराने बांधों पर नहरों की जलग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ 64 साल पुरानी ग्वालियर-चंबल संभाग की चंबल-नहर प्रणाली का उद्धार नए तरीके से किया जाएगा। तय है, ये नदियां निर्धारित अवधि में जुड़ जाती हैं, तो सिंचाई के लिए कृषि भूमि का रकबा बढ़ने के साथ अन्न की पैदावार बढ़ेगी। किसान खुशहाल होंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

नदियों की धारा मोड़ने का दुनिया में पहला उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है। इंद ने सिंचाई और पेयजल की सुविधा सुगम कराने की दृष्टि से सिंधु नदी की धारा को मोड़ा था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को पहाड़ तोड़कर भगवान परशुराम ने मोड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान की जो परिकल्पना की थी, उसे नरेंद्र मोदी ने साकार करने की शुरूआत केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ कर दी थी। ये परियोजनाएं जल-शक्ति अभियान ‘केच द रन’ के तहत अमल में लाई जा रही हैं। बाढ़ और सूखे से परेशान देश में नदियों के संगम की परियोजना मूल रूप ले रही है, यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। इन परियोजनाओं को जोड़ने का अभियान सफल होता है तो भविष्य में 57 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा-चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई

के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा।

वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है। हालांकि पर्यावरणविद् इन परियोजनाओं को यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ने से इनकी अतिरलता खत्म होगी, नतीजतन नदियों के विलुप्त होने का संकट बढ़ जाएगा। कृत्रिम रूप से जीवनदायी नर्मदा और मोक्षदायिनी



क्षिप्रा नदियों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके थे। चूँकि ये दोनों नदियां मध्य-प्रदेश में बहती थीं, इसलिए इन्हें जोड़ा जाना संभव हो गया था। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की तैयारी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बहुत पहले से जुटी थीं। इस परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें होने के कारण एकमत नहीं हुई। कालांतर में केंद्र समेत उग्र और मप्र में भी भाजपा की सरकारें बन गईं। नतीजतन परियोजनाओं पर सहमति बन गई। केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की ओर बहने के बाद बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। वहीं बेतवा नदी मध्य-प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तर-प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना पर भूमि अधिग्रहण के साथ

तेज गति से बांधों एवं नहरों का काम शुरू हो गया है।

जीवनदायी नदियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। नदियों के किनारे ही ऐसी आधुनिकतम बड़ी सभ्यताएं विकसित हुईं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। सिंधु घाटी और सारस्वत (सरस्वती) सभ्यताएं इसके उदाहरण हैं। भारत के सांस्कृतिक उन्नयन के नायकों में भारीरथी, राम और कृष्ण का नदियों से गहरा संबंध रहा है। भारतीय वांगमय में इंद्र और कुबेर विपुल जलराशि के प्राचीनतम

पर्यावरण संस्था ने मरी हुई नदी तक घोषित कर दिया है।

प्रस्तावित करीब 120 अरब डालर अनुमानित खर्च की नदी जोड़ों परियोजना को दो हिस्सों में बांटकर अमल में लाया जाएगा। एक प्रायद्वीप स्थित नदियों को जोड़ना और दूसरे, हिमालय से निकली नदियों को जोड़ना। प्रायद्वीप भाग में 16 नदियां हैं, जिन्हें दक्षिण जल क्षेत्र बनाकर जोड़ा जाना है। इसमें महानदी, गोदावरी, पेनार, कृष्णा, पार, तापी, नर्मदा, दमनगंगा, पिंजाल और कावेरी को जोड़ा जाएगा। पश्चिम के तटीय हिस्से में बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ा जाएगा। इस तट से जुड़ी तापी नदी के दक्षिण भाग को मुंबई के उत्तरी भाग की नदियों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की जलधारा पूर्व दिशा में मोड़ी जाएगी। यमुना और दक्षिण की सहायक नदियों को भी आपस में जोड़ा जाना इस परियोजना का हिस्सा है। हिमालय क्षेत्र की नदियों के अतिरिक्त जल को संग्रह करने की दृष्टि से भारत और नेपाल में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों पर विशाल जलाशय बनाने के प्रावधान हैं। ताकि वर्षाजल इकट्ठा हो और उत्तर-प्रदेश, बिहार एवं असम को भंयकर बाढ़ का सामना करने से छुटकारा मिले। इन जलाशयों से बिजली भी उत्पादित की जाएगी। इसी क्षेत्र में कोसी, घाघरा, मेच, गंडक, साबरमती, शारदा, फरक्का, सुन्दरवन, स्वर्णरेखा और दमोदर नदियों को गंगा, यमुना और महानदी से जोड़ा जाएगा। करीब 13,500 किमी लंबी ये नदियां भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में अठखेलियां करती हुई मनुष्य और जीव-जगत के लिए प्रकृति का अनूठा और बहुमूल्य वरदान बनी हुई हैं। 2528 लाख हेक्टेयर भू-खण्डों और वनप्रतारों में प्रवाहित इन नदियों में प्रति व्यक्ति 690 घनमीटर जल है। कृषि योग्य जल 1411 लाख हेक्टेयर भूमि में से 546 लाख हेक्टेयर भूमि इन्हीं नदियों की बढौलत प्रति वर्ष सिंचित की जाकर फसलों को लहलहाती है।

दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, अलनीनो और बदलते वर्षा चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है। इसलिए नदी जोड़ो परियोजनाओं को भविष्य के लिए लाभदायी माना जा रहा है।

मुद्दा

आरके सिन्हा

लेखक पूर्व सांसद हैं।



‘एक देश एक चुनाव’ के सपने को साकार करने की तरफ देश बढ़ रहा है। बेशक,लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। भारत में ‘एक देश-एक चुनाव’ का विचार एक ऐसा विषय है जिस पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे देश को कई फायदे होंगे, वहीं कुछ लोग इसके कुछ नुकसान भी बताते हैं। पर ये सच है कि बार-बार चुनाव कराने में काफी पैसा खर्च होता है। एक साथ चुनाव कराने से इस खर्च को काफी ह्राद थे कम किया जा सके । चुनावों में सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की भारी संख्या में तैनाती करनी पड़ती है। जाहिर है, बार-बार चुनाव होने से कामकाज में बाधा तो आती ही है साथ ही संसाधनों का भारी दुरुपयोग भी होता है। एक साथ चुनाव कराने से इस समस्या को दूर काफी हद तक कम किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के बाद सरकार एक देश- एक चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इससे लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव सभी एक साथ होंगे। यह सब 100 दिनों के अंदर ही संपन्न होगा। सरकार का मानना है कि इससे देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है। यह मामला किसी एक दल का

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए

उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. डी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड,

इंदौर से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी

संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय

वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल

स्थानीय संपादक - हेमंत पाल

प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MP/PHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्या कमी है ‘एक देश एक चुनाव’ में?

नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में है। यह सबको पता है कि देश में बार-बार चुनाव होने से जनता और सरकारी अधिकारियों का समय और संसाधन बर्बाद होता है। एक साथ चुनाव कराने से यह सब नहीं होगा। एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता में सुधार आएगा, क्योंकि सरकार को बार-बार चुनावों की चिंता नहीं



करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव होने से प्रशासन पर दबाव कम होगा और वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ‘एक देश, एक चुनाव’ से कई मसलों का हल हो जाएगा। चुनावों की अवधि कम हो जाने से, शासन और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

एक देश, एक चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी का पुराना एजेंडा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी जी इसकी वकालत करते रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में 2 सितंबर 2023 को कोविंद कमिटी बना कर उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था। निश्चित रूप से बार-बार चुनाव होने से सरकारें नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने में झिझकती हैं। एक साथ चुनाव होने से सरकारों को स्थिरता मिलती है और वे बेहतर ढंग से काम कर पाती हैं। एक बात

और कि बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक दल विकास के मुद्दों से भटक जाते हैं और चुनाव जीतने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक दलों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक अवसर मिलता है।

‘एक देश-एक चुनाव’ के विपक्ष में तर्क में कुछ पिलपिले तर्क आ रहे हैं। जैसे कि



राष्ट्रीय चुनावों के साथ-साथ राज्यों के चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से लोकतंत्र कमजोर हो सकता है क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर एक ही राजनीतिक दल का दबदबा हो सकता है। यह सब तर्क कमजोर है।

दुनिया के कई देशों में अलग-अलग चुनाव व्यवस्थाएं हैं। कुछ देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, जबकि कुछ देशों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं।

स्वीडन, बेलजियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव एक साथ किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। बहरहाल, एक देश-एक चुनाव से देश के आम जनमानस में राष्ट्र की अवधारणा सशक्त होगी। भारत में साल 1967 तक

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। साल 1947 में आज़ादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। उस समय राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव साथ ही कराए गए थे, क्योंकि आज़ादी के बाद विधानसभा के लिए भी पहली बार चुनाव हो रहे थे। उसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए थे। यह सिलसिला पहली बार उस वक़्त टूटा था जब केरल में साल 1957 के चुनाव में ईएमएस नंबूदरीबाद की वामपंथी सरकार बनी। साल 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभा जल्दी भंग हो गई और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, इसके अलावा साल 1972 में होनेवाले लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराए गए थे। साल 1967 के चुनावों में कांग्रेस को कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे कई राज्यों में विरोधी दलों या गठबंधन की सरकार बनी थी। इनमें से कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं और विधानसभा समय से पहले भंग हो गई थी। यह भी माना जा रहा है कि एक साथ चुनाव होने से मतदाता भारीगदारी में वृद्धि हो सकती है क्योंकि लोगों को बार-बार मतदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि ‘एक देश एक चुनाव’ को दलागत आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर हर स्तर पर खुल कर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाना चाहिए। अगर इसे भाजपा या मोदी जी के किसी एजेंडे के रूप में देखा गया तो यह सही नहीं होगा। अभी तक जो विपक्षी नेता ‘एक देश एक चुनाव’ के विचार का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना चाहिए कि क्या उन्हें बार-बार चुनावी रणभूमि में उतरना पसंद है?

छुट्टियां, पर्यटन और हमारी सेहत

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं।



दि संबर् का अंत आ रहा है। यह इस साल की समाप्ति और नए वर्ष के आरंभ का समय भी है। यही बड़े दिन की छुट्टियों का भी वक़्त है। बात जब छुट्टियों की होती है तो हर घर में लगभग चर्चा का विषय होगा कि सर्दियों की छुट्टियों में कहा घूमने जाया जाए। कुछ लोग गर्मी की तलाश में रहेंगे तो कुछ सर्दी में बर्फ का आनन्द लेना चाहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान हम नहीं ख़ूब पा रहे हैं। जैसे घूमने और जीवन को सुखमय क्षणों में व्यतीत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?

हममें से सबका जवाब अलग-अलग होगा। कुछ परिवार के साथ घूमने को प्राथमिकता देंगे, कुछ दोस्तों के साथ को और कुछ एकल ही घूमने में स्वयं को आरामदायक महसूस करेंगे। सब अपने अनुभव तो बताएंगे, पर किसी का भी ध्यान दो महत्वपूर्ण बातों पर शायद ही जाए। पहला सेहत जिसके बिना जीवन का हर सुख अधूरा है। हम कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी परिवार को महत्व दें। हमारे बहुत सारे दोस्त हो। तब भी अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो सब सुख हमारे लिए ग़ीण है। हमारा साथ अगर हमारा शरीर नहीं दे पा रहा है तो समझिए कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। हम किसी की दया के पात्र तो हो सकते हैं, लेकिन सुख -दुख के साथी कभी नहीं हो सकते। हम अपने को एक बोझ मानने लगते हैं।

हर पल एक उम्मीद से सबको देखते हैं कि कोई चाहे हमसे हमारी सारी दौलत ले लें, पर

हमें स्वस्थ कर दें। यहां कुछ भांतियां भी है कि अगर आप बोड़ी बनाते हैं,आपके मसल्स है, या आप डाइटिंग करके दुबले है, तो आप स्वस्थ हैं।यह केवल एक भाँति है

स्वस्थ होने का दुबले होने से कोई तालमेल ही नहीं है। आज के जलवायु और खान-पान को देखते हुए कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसलिए आन्तरिक रूप से स्वस्थ होने की बहुत जरूरत है। हमारे आसपास का पर्यावरण भी हमारे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालता है। लोबल वार्मिंग के चलते हर मौसम ने अपना अंदाज बदल लिया है। जिसका



कुप्रभाव हम पर पड़ रहा है, जिसे हम अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ना तो गर्मी में पहले जैसी तपिश है, जिसे सावन की बूँदें ठंडक दें सकें और ना ही सर्दियों में अपनी बर्फिली पहाड़ियों में कशिश बची है। ग़लती मानव की है, पर खामियाजा धरती के हर प्राणी को भुगतान पड़ेगा। बर्फ के पहाड़ भी मानव मन के भीतर जमी स्वार्थी परतों पर आश्चर्यचकित हैं। हमें यह समझना होगा कि पहाड़ों को भी सर्द भावनाओं की जरूरत है और गर्मी को भी अपनी भावनाओं को छलकाने का अधिकार है। समय आ गया है, जब हम प्रकृति का सम्मान करते हुए। प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखते हुए प्रकृति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।

जनसंख्या की गाड़ी,कैसे बढ़े अगाड़ी

चीन,दक्षिणी कोरिया और ईरान आदि देशों की आबादी

निरंतर घट रही है। नए बच्चे कम पैदा होने से जापान बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। खुद की न सही देश,समाज विश्व के बारे में भी कुछ तो सोचो।'

पती बीच में ही नन्थू की बात काटकर बोली- ‘‘यह मीडिया और राजनेता मिलकर तुमको पागल करके छोड़ेंगे।कभी कहते हैं-‘बच्चे दो ही अच्छे’‘हम दो हमारे दो’। अब कह रहे हैं बच्चे तीन पैदा करो।

किसी जमाने में किसी सरकार ने ही कहा था कि बढ़ती जनसंख्या ही गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। जनसंख्या कम करने का अभियान चलाया गया। परिवार नियोजन के लिए ऐसा शिकजा कसा गया था कि अनिवार्य नसबंदी की आँधी चल पड़ी थी। भिखारी और कुँवारे तक गेहूँ के साथ घुण की तरह चपेट में आ गए थे। उसके बाद जनसंख्या में तेजी गिरावट आई। ब्रेक लगाते-लगाते भी जनसंख्या की गाड़ी ने

विश्व में सबको पछाड़ कर भारत को आगे कर डाला।’’

पती ने कहना जारी रखा- ‘‘ अब इक्कीसवीं सदी की महिलाएँ पहले जैसी नहीं रही। शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उनकी आँखें खोल दी है। पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। अलबत्ता तो वे शिक्षा और कैरियर को लेकर इतनी सचेत हैं कि जल्दी शादी करना ही नहीं चाहती। कुछ की विवाह के लड्डूओं में अब खास दिलचस्पी ही नहीं रही।

पती की ज्ञान और समझ से भरी बातें सुनकर नन्थू ने भी अपना सूर बदलने में ही भलाई समझी। तत्काल उसने पती के सूर में सूर मिलाकर कहा- ‘‘तुम्हारी बात सही है भाय्यवान, मनुष्य को अपने छोटे छोटे समुदायों के संकीर्ण स्वार्थों के घेरों से निकलकर एक बड़े समुदाय मानव समाज में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। भारतीय संस्कृति की ‘‘माता पृथ्वी ,पुत्रो अहम्’’ यानि हम सबकी माता पृथ्वी है और हम सब इसकी संतान है।



दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

दुनिया भर के तमाम विवादों का मूल कारण किसी एक पक्ष का एकतरफा सोच ही हुआ करता है। जिसके चलते समाधान के अभाव में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। लगातार तमाम तरह के बढ़ते विवादों के चलते न्याय की अपेक्षा करने वालों की कतार इतनी लंबी हो गई है कि अंतिम न्याय पाने की कोशिश में जिंदगी का एक बड़ा भाग जाया हो जाता है। कभी-कभी तो व्यवस्थित रूप से जोड़ घटाव करने के उपरांत हासिल कुछ नहीं बचता। या कभी बचता भी है, तो लगभग न के बराबर। बात सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, अपितु लंबी प्रतीक्षा और मानसिक संताप का भी यदि आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करें, तो चौकाने वाले परिणाम हमारे सामने होंगे।

हालांकि जमाने में सब कुछ निर्विवाद नहीं हो सकता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उभय पक्ष अपनी-अपनी जगह लगभग सही हो। ऐसी स्थिति में जब समाधान की कोई सूरत ही नजर नहीं आती हो, तब न्यायपालिका का सहारा लिया जाए, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कभी-कभी किसी मामले को लंबे समय तक टालने की दृष्टि से भी न्यायपालिका का सहारा लिया जाने लगा है। यही कारण है कि देश भर की तमाम अदालतों में मुकदमों की भरमार नजर आती है। ऐसी स्थिति में जिनके लिए वास्तव में न्याय अपेक्षित होता है, उन्हें भी लंबी कतार में लगने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न्याय पाने की प्रक्रिया समय एवं धन साध्य हो जाती है।

इन संदर्भों में आपके हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक

हम ही सही हैं, यह सोच सही नहीं



हो जाता है कि हम सुलह का रास्ता अखिर्यार करने की दिशा में गंभीरता का परिचय दें। वैसे भी न्यायपालिका की मध्यस्थता में अनेक तरह के विचाराधीन मामलों का लोक

अदालत द्वारा सुखद पटाक्षेप करने का प्रयास किया जाता रहा है। जिसमें उभय पक्ष के अभिभाषक वर्ग की अत्यंत सराहनीय भूमिका निकल कर आती रही है। समय की मांग के

अनुरूप यह सिलसिला अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए। इससे कुल मिलाकर देश में उपलब्ध शारीरिक और मानसिक श्रम शक्ति का और भी समुचित दोहन होने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। क्योंकि देश की ऊर्जा एवं चेतना का एक बड़ा भाग न्याय की अपेक्षा में खोया-खोया नजर आता है।

दरअसल त्वरित न्याय के लिए देश में ऐसा वातावरण बनाया जाना जरूरी है कि अक्वल तो विवाद हो ही नहीं, और हो तो भी सीमित मात्रा में। इसके लिए हर एक आदमी को एकतरफा सोच की स्थिति से उबरना होगा, इस दिशा में सामाजिक प्रभाव एवं दबाव भी कारगर हो सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका एवं अभिभाषक वर्ग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। वैसे तो न्यायपालिका एवं अभिभाषक वर्ग का हर संभव प्रयास त्वरित न्याय की दिशा में ही होता है। लेकिन मुकदमों की

बहुतायत के चलते इसका प्रत्यक्ष परिणाम कहीं दिखाई नहीं देता। जिसका नतीजा होता है कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख ही मिलती चली जाती है।

इसके चलते विलंबित न्याय, अन्याय के प्रतिरूप में ही दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में तथाकथित त्वरित न्याय हेतु कुछ एक मामलों को तो बिना कानूनी प्रावधान का सहारा लिए गलत रास्ता भी अपना लिया जाता है। जिसके चलते कानून और व्यवस्था पर भी आंच जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, मुद्दे की बात यह कि उपरोक्त स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यदि एकतरफा विचारधारा के बजाय निष्पक्ष एवं तटस्थ दृष्टि से किसी मामले का आकलन किया जाए, तो सहज रूप से अदालत से परे मामले का समाधान संभव हो सकता है। इस दिशा में सामाजिक नेतृत्व अपने समाज में ऐसा वातावरण निर्मित कर सकता है कि विभिन्न समाजों के बीच एक संतुलन का वातावरण निर्मित हो सके।

जाहिर है कि जब इस प्रक्रिया का विस्तार होने लगेगा, सारा का सारा सामाजिक परिवेश ही शांति का पुजारी बन जाएगा। अन्यथा हालात ऐसे ही रहे तो दिनोंदिन बढ़ती मुकदमों की संख्या न्याय को और भी अधिक समय व धन साध्य बनाकर रख देगी। जिसके चलते सामाजिक सद्भाव पर तो विपरीत असर पड़ेगा ही अपितु कानून और व्यवस्था के समक्ष भी गंभीर चुनौती उपस्थित हो सकती है। वैसे भी अधिकतर धन संपत्ति एवं अपराध के मामले विचाराधीन रहा करते हैं। ऐसे में धन संपत्ति के मामले में आपराधिक वर्ग के हस्तक्षेप को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकेगा। यह स्थिति आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर भारी भी पड़ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर कोई अपने एकतरफा सोच विचार का परित्याग करके चले।

छत्तीसगढ़ में नया पर्यटन स्थल धुड़मारास

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मग जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

देश का छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल प्रदेश है। य्ं तो छत्तीसगढ़ नक्सलियों के आतंक के केन्द्र के रूप में देशभर में ज्यादा प्रसिद्ध है। किन्तु कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ के वनों से आच्छादित क्षेत्र में आदिवासियों की ही ग्राम सभा धुड़मारास की सामुदायिक वन संसाधन समिति द्वारा बनाए गए

सुरक्षा के लिए पहरेदारी करते हैं। सबकी ड्यूटी लगती है। जो व्यक्ति पहरेदारी में नहीं पाया जाता है, उस पर अर्थदंड लगाया जाता है। जो उसको देना अनिवार्य होता है।

ग्राम सभा धुड़मारास के युवा अध्यक्ष श्री सोनादार बघेल अपनी ग्राम सभा के गठन की जानकारी देते हुए उत्साह से बताते हैं कि हमारे गाँव में

खुद को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि खुद इतना कमा सके कि अपना परिवार अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए उसने अपने जैसे मित्रों का सहयोग लेकर अपने ग्राम में ग्राम सभा का गठन किया। फिर इसके बाद सामुदायिक वन प्रबंधक समिति और इको विकास समिति का गठन किया। ग्राम सभा धुड़मारास के अध्यक्ष श्री बघेल ने इस गाँव को पर्यटन के आकर्षण का केन्द्र कैसे बनाया ? इसकी कहानी बताते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने बाहर से बांस बुलाकर उससे नाँव बनाई। इस नाँव को ग्राम के बीच से बहने वाली नदी में चलाया। इसका उन्होंने बाम्बु राफ्टिंग नाम दिया। ग्राम सभा द्वारा नदी में बांस की नाँव चलाकर बाम्बु राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति से 200

सब पूछने पर वे उत्साह से बताते हैं, कि हम कुछ करना चाहते थे, किन्तु क्या करें? यह समझ में नहीं आ रहा था। तब हमारे यहाँ के वनमंडलाधिकारी महोदय ने हमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण हम यह सब कर सके हैं। युवा अध्यक्ष बघेल बताते हैं कि बाम्बु राफ्टिंग और कायाकिंग के अलावा उन्होंने गाँव में पर्यटकों को रहने और छत्तीसगढ़ का भोजन उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे भी बनाएँ हैं। यहाँ पर्यटकों को छत्तीसगढ़ का भोजन और रहने की सुविधा रियायती दर पर उपलब्ध कराते हैं।

यदि आदिवासियों को सही मार्गदर्शन और सहयोग मिल जाए तो वे आत्मनिर्भरता का अनुभव उदाहरण



एक नए पर्यटन केन्द्र के रूप में यह ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा है। छत्तीसगढ़ के दोंवाड़ा से करीब 70 किलोमीटर दूर सघन वन में ग्रामसभा धुड़मारास है। इस ग्रामसभा ने अपनी सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति गठित की है। इस समिति में ग्राम के सभी 45 घरों से 2-2 सदस्य लिए गए हैं। इन 2 सदस्यों में से एक पुरुष और एक महिला है। इन सभी की जिम्मेदारी यह है कि ये 24 घंटे अपने क्षेत्र के वन और जल की

केवल 45 घर हैं। ग्राम सभा के गठन के लिए प्रत्येक घर से एक पुरुष और एक महिला को लिया गया है। इस प्रकार कुल 90 सदस्य हैं। सभी आदिवासी हैं। ये सब अपने गाँव के जल और जंगल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केवल 5 वीं तक पड़े युवा अध्यक्ष श्री बघेल बताते हैं कि पहले घर चलाना बड़ा मुश्किल होता था। सब जैसे-तैसे अपना परिवार चला रहे थे। एक दिन ऐसे ही उन्हें ध्यान आया कि सरकार या किसी भरोसे रहने की जरूरत नहीं। हमें

रूपए शुल्क लेना तय किया गया। प्रत्येक नाँव में 4 लोगों के बैठने के लिए बाँस से ही आसने-सामने बैच बनाई गई। इसमें अनिवार्य रूप से पर्यटकों को लाइफ जैकेट भी पहनाई जाती है। बाम्बु राफ्टिंग के अतिरिक्त एक नाँव में एक व्यक्ति को घुमाने ले जाने की भी व्यवस्था की गई है, जिसका नाम उन्होंने दिया है, कायाकिंग। ग्राम सभा ने प्रति व्यक्ति इसका शुल्क 100 रूपए तय किया है। श्री बघेल को यह सब जानकारी कहीं से और कैसे मिली ? यह

प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हैं, ग्राम सभा धुड़मारास। कुछ महीनों पहले ही शुरू हुई इस पहल के कारण आज गाँव के 45 घरों के सभी परिवारजन सुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आज ग्राम सभा धुड़मारास द्वारा पर्यटकों के लिए दी गई सुविधा बाम्बु राफ्टिंग और कायाकिंग देशभर में प्रसिद्ध हो चुकी है। कोई भी इसे गूगल पर देख कर आ सकता है। ग्राम सभा धुड़मारास हर पर्यटक के स्वागत के लिए तैयार है।

खेल जगत

नूपेन्द्र अभिषेक नूप

लेखक स्तंभकार हैं।

भारतीय क्रिकेट हमेशा से स्पिन गेंदबाजों का गढ़ रहा है। इस परंपरा ने क्रिकेट की दुनिया को अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, और रविचंद्रन अश्विन जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी दिए हैं। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, और उनके इस निर्णय ने क्रिकेट प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। अश्विन ने न केवल भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि विश्व क्रिकेट में भी अपने कौशल का परचम लहाया।

रविचंद्रन अश्विन का जन्म 17 सितंबर 1986 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट बेड्स स्कूल से प्राप्त की और बाद में एसएएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। हालांकि उनका झुकाव हमेशा क्रिकेट की ओर रहा। शुरू में एक बल्लेबाज के रूप में खेलने वाले अश्विन ने जल्दी ही महसूस किया कि उनकी असली प्रतिभा ऑफ स्पिन गेंदबाजी में है। अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच से की। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई और अपने पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

रविचंद्रन अश्विन का क्रिकेट करियर आंकड़ों के लिहाज से अद्वितीय रहा है। उन्होंने 94 टेस्ट मैचों में 474 विकेट लिए, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक बनाता है। इसके अलावा, वनडे और टी20 प्रारूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अश्विन ने न केवल गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी भारतीय टीम को मजबूती दी। उन्होंने 5 शतक और 13 अर्धशतक बनाए हैं, जो यह दर्शाता है कि वे एक ऑलराउंडर के रूप में कितने सक्षम थे। अश्विन ने वनडे में 151 विकेट और टी20 में 72 विकेट लिए। हालांकि, उनका प्रमुख योगदान टेस्ट क्रिकेट में ही देखा गया।

अश्विन का गेंदबाजी स्टाइल उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी में विविधता, फ्लाइट, और गति का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। उनकी 'कैरम बॉल' ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिलाई। उनकी गेंदबाजी में गहराई और बल्लेबाजों को पढ़ने की क्षमता उनकी सफलता का मूल कारण रही है।



अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के संन्यास के बाद भारतीय टीम में एक ऐसे स्पिनर की जरूरत थी जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकाल सके और कठिन परिस्थितियों में टीम का साथ दे सके। अश्विन ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कुंबले की तरह, अश्विन ने भी टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता और दृढ़ता दिखाई। हरभजन की तरह, उन्होंने भी आक्रामकता और बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाने की कला सीखी। अश्विन की सफलता केवल भारतीय धरती तक सीमित नहीं रही। उन्होंने जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी गेंदबाजी हमेशा यादगार रही है। 2016 में, अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला, जो उनकी प्रतिभा और योगदान को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है।

अश्विन का संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत जैसा है। हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेलना जारी रखने का संकेत दिया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी अनुपस्थिति को महसूस किया जाएगा। उनके संन्यास का फैसला कई कारणों से लिया गया हो सकता है, जिनमें उम्र, शारीरिक थकान, और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की

भावना शामिल हो सकती है। अश्विन का प्रभाव केवल उनके प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और स्पिन गेंदबाजी की नई परिभाषा गढ़ी है। उनकी सोच, तकनीक, और रणनीतियां भारतीय क्रिकेट के लिए एक धरोहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला और कई मैच जिताए। उन्होंने दिखाया कि एक स्पिनर भी ऑलराउंडर बन सकता है। अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर टीम में हैं, लेकिन अश्विन जैसी विविधता और अनुभव हासिल करने में समय लगेगा।

रविचंद्रन अश्विन का करियर भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज रहेगा। उन्होंने न केवल स्पिन गेंदबाजी को नई ऊंचाई दी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों को कई यादगार पल भी दिए। उनके संन्यास के बाद टीम में उनकी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मानदंड आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। अश्विन को इस नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं, और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए हमेशा आभार।

कैंसर वैक्सीन

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषक

रुस द्वारा कैंसर रोकने के लिए की गई वैक्सीन की घोषणा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह की घोषणाएं आमतौर पर आशा और सकारात्मकता की भावना को बढ़ाती हैं। कैंसर जैसी गंभीर और जीवन के लिए खतरा मानी जाने वाली बीमारी के संभावित इलाज की ऐसी खबर सुनकर मरीजों और उनके परिवारों में एक अलग सा सुकून महसूस होता है। वे भविष्य को लेकर अधिक आशावादी हो सकते हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति में सुधार लाने का कार्य कर सकता है।

कई बार मरीजों और उनके साथ वालों में कैंसर को लेकर जो भय होता है, वह ऐसी बातों से कम हो जाता है। लोग इसे जीवन की अनिश्चितता से जुड़े भय के कम होने के रूप में देखते हैं। डैथ फोबिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बेहद गहरा होता है, और इस तरह की घोषणा से लोगों के दिमाग में यह विश्वास पनपता है कि भविष्य में इस बीमारी का इलाज संभव हो जाएगा। यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की भावना को कम करने में मदद करता है।

यह स्वयं पर नियंत्रण (self-efficacy) की भावना को मजबूत करता है, क्योंकि लोग यह महसूस करते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर उनका नियंत्रण है। कैंसर के मरीज अक्सर लंबी और थकाऊ उपचार प्रक्रिया से गुजरते हैं,

आशा, सकारात्मकता और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का गहरा प्रभाव



जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लेकिन कैंसर के टीके की खबर उन्हें यह विश्वास दिला सकती है कि उनका संघर्ष अनिश्चित काल तक जारी नहीं

रहेगा। इससे डिप्रेशन और चिंता के स्तर में कमी आ सकती है। इस घोषणा के कुछ संभावित नकारात्मक प्रभाव

सकता है। कैंसर से पीड़ित लोगों के प्रति समाज में सहानुभूति और समझ का स्तर बढ़ सकता है। जब लोग यह समझते हैं कि कैंसर अब एक 'असाध्य बीमारी'

नहीं रही, तो कैंसर से जुड़े कलंक और नकारात्मक सामाजिक धारणाएं धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। इससे मरीजों का आत्म-सम्मान और सामाजिक समर्थन प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सकती है। इस घोषणा का एक अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू हेल्थ केयर सिस्टम और विज्ञान पर लोगों के विश्वास से जुड़ा है। जब किसी सरकार या वैज्ञानिक संगठन द्वारा किसी घातक बीमारी के इलाज के लिए नई खोज की घोषणा की जाती है, तो आम पब्लिक का विश्वास हेल्थ केयर सिस्टम और वैज्ञानिकों में बढ़ता है। यह विश्वास महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों का झुकाव नई चिकित्सा तकनीकों और टीकाकरण के प्रति बढ़ता है। जो लोग पहले चिकित्सा विज्ञान और टीकाकरण के बारे में संशय में रहते थे, वे अब वैज्ञानिक शोध के महत्व को स्वीकार कर पाते हैं। कुल मिलाकर, रूस द्वारा कैंसर के टीके की घोषणा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। यह आशा, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक समर्थन को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि लोगों को अवास्तविक अपेक्षाओं से बचाया जाए और उन्हें वास्तविकता के बारे में जागरूक किया जाए। इस घोषणा का सही संदेश जनता तक पहुंचाना और उम्मीदों को वास्तविक बनाए रखना कैंसर चिकित्सकों, मनोचिकित्सकों और मीडिया की जिम्मेदारी है।

धान खरीदी केद्रों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

रानीपुर में बंद पड़ी खरीदी को तत्काल करवाया चालू



बैतूल। धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। निर्धारित स्लॉट बुकिंग के अनुरूप समय पर किसानों से गुणवत्तापूर्ण रुप से खरीदी की जाए। यह निर्देश कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बुधवार को घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सबसे

पहले रानीपुर में गायत्री वेयरहाउस धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खरीदी केंद्र पर सर्वेयर के अभाव में खरीदी बंद पाई गई। किसानों ने बताया कि उन्हें विगत दो दिनों से अपनी धान बेचने में काफी परेशानी हो रही है। जिस पर कलेक्टर ने उपार्जन संबंधी अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल सर्वेयर को नियुक्त कर केंद्र पर खरीदी चालू करवाई। उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम को भी अपने क्षेत्र में सुचारु रूप से खरीदी कराने के निर्देश दिए।

सुव्यवस्थित ढंग से खरीदी की जाए – इसके बाद कलेक्टर श्री सूर्यवंशी रानीपुर स्थित खरीदी केंद्र जुआड़ी पहुंचे। उन्होंने केंद्र पर किसानों से चर्चा कर खरीदी की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि खरीदी केंद्र पर किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने घोड़ाडोंगरी में खरीदी केंद्र मंगलम वेयरहाउस एवं बालाजी वेयरहाउस का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां खरीदी धीमी गति से होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि केंद्र पर तौलकांटो, हम्मालों आदि आवश्यक संसाधन बढाएं और खरीदी तेजी से की जाए।

केन्द्र पर पहले आने वाले किसानों से पहले तुलाई की जाए – कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने केंद्र प्रभारियों को सख्त हिदायत दी कि किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। स्लॉट बुकिंग के अनुरूप पहले आने वाले किसानों की पहले तुलाई की जाए। व्यवस्थित तुलाई के लिए खरीदी केंद्र पर टोकन की व्यवस्था भी करें। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने केंद्र प्रभारी एवं उपार्जन संबंधी अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदे केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं रहे। केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बैठक इत्यादि की उतम व्यवस्थाएं की जाए।

समर्थन मूल्य से ज्यादा मंडी में बिक रहा सोयाबीन, क्योंकि फेल किए जा रहे सैपल

826 किसानों से 2758

मैट्रिक टन सोयाबीन की

खरीदी, 8.51 करोड़ का कर

भी दिया भुगतान

संजय द्विवेदी, बैतूल। किसानों को फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए सरकार समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी कर रही है, जबकि बाजार से अधिक दाम, समर्थन मूल्य पर दिया जा रहे हैं। फिर भी किसान समर्थन मूल्य में सोयाबीन बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके पीछे किसानों का तर्क है कि खरीदी सेंट्रों पर सैपल फेल किया जा रहा है। साथ ही रुपए मिलने में भी देरी हो रही है। यहीं वजह है कि रोजाना बड़ी संख्या में सोयाबीन मंडी में बिकने के लिए पहुंच रही है। किसान सोधे व्यापारियों को ही सोयाबीन बेच रहे हैं। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार समर्थन मूल्य में 826 किसानों ने 2758.55 मैट्रिक टन सोयाबीन बेचा है, जबकि इससे कई अधिक मात्रा में सोयाबीन मंडी में बिक चुका है। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए मापदंड कटिन् है। किसान जब सेंटर पर सैपल लेकर जाता है



तो एफएक्यू क्वालिटी के अनुसार सोयाबीन अमानक बताकर लौटा दिया जाता है। साथ ही जो किसान केंद्र पर सोयाबीन बेचते हैं, उन्हें 8 से 10 दिन में रुपए मिलते हैं। खुले बाजार व मंडी में व्यापारी सोयाबीन सभी क्वालिटी की खरीद रहे हैं। मंडी अनुबंध के अनुसार तीन दिन में राशि देने व छोटे किसानों को नकद राशि मिल जाती है। जिससे किसान कम भाव में उपज बेच देता है।

किसान बोले– ऋण की काटकर मिलती है राशि – किसानों ने बताया खरीदी केन्द्रों पर सोयाबीन खरीदी के लिए मापदंड निर्धारित किये गये है। मापदंड

अनुरूप उपज होने पर ही सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। किसानों का कहना है कि अक्टूबर में हुई बारिश से खेतों में तैयार सोयाबीन फसल भीग गई। बार-बार बारिश होने से सोयाबीन को पूरी तरह सूखने का समय नहीं मिला। सोयाबीन काली व कमजोर रह गई, जो एफएक्यू क्वालिटी के मानक अनुसार नहीं है। यदि किसान केन्द्रों पर सैपल लेकर भी जाते है तो फेल कर देते है। किसानों को केंद्र तक सोयाबीन ले जाने में अधिक खर्च वहन करना पड़ रहा है। ऊपर से जो राशि मिलती है, उसमें देरी के बाद सोयायटी के ऋण की राशि भी काट ली जाती है। इससे किसानों

विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे का मास्टर स्ट्रोक

आमला विस के लिए 57 करोड़ के विकास कार्य कराए स्वीकृत

संजय द्विवेदी, बैतूल। जिले के सभी पांच विधानसभा सीटों पर भले ही भाजपा ने परचम लहराया हो, लेकिन वास्तविकता पर गौर करें तो जिले के आमला विधानसभा सीट के

विधायक डॉ योगेश पंडग्रे ने अपने विधानसभा क्षेत्र आमला में विकास के कार्यों की झाड़ियां लगाकर भाजपा का कुछ ऐसा परचम लहरा दिया है कि इस क्षेत्र में ऐसा कभी हुआ है, ना होने वाला है। यानी सही मायने में अगर कहा जाए तो डॉ. योगेश पंडग्रे का विकास के कार्यों में अपने विस क्षेत्र के लिए मास्टर स्ट्रोक है। चूँकि इसके पहले हाल



ही में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी में नई विद्युत इकाई की स्थापना को लेकर हो रही मांग को उन्होंने स्वीकृत करने में कामयाब हुए, साथ ही इस क्षेत्र में सीमेंट की एक बड़ी फैक्ट्री भी लगने जा रही है, उसमें विधायक डॉक्टर पंडग्रे की अहम भूमिका है। इस दो बड़े कार्यों की सीमागत उन्होंने जो दी है इससे पाथाखेड़ा सारणी क्षेत्र को उन्होंने उजड़ने से बचाने का काम किया है। इसके साथ ही अब 57 करोड़ से अधिक का सड़क पुन पुलिया और नाली आदि के विकास कार्यों के लिए उन्होंने राशि मंजूर कराने में सफलता हासिल की है, जो कि जिले की अन्य विधान सभा क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक आमला विधानसभा क्षेत्र के लिए राशि स्वीकृत हुई है। जानकारी के मुताबिक बैतूल जिले के आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. योगेश पंडग्रे ने अपने विधानसभा आमला- सारणी क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 पुल पुलिया सड़क के लिए 57 करोड़ से अधिक की राशि लेने में कामयाब हुए हैं। अगर सही मायने में कहा जाए तो इतनी बड़ी राशि से निश्चित ही आमला विधानसभा क्षेत्र में सड़कों

की जाल बिछेगी, वही पुल पुलिया आदि बनने से इस विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि लंबे समय से सतपुड़ा थर्मल पावर सेंटर सारणी को

उजड़ने से बचाने के लिए बिजली की नई इकाई की स्थापना के लिए मांग हो रही थी। क्षेत्रवासियों को इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर डॉ. योगेश पंडग्रे भी काफी गंभीर थे और उन्होंने इस आशय की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने रखी थी, जिसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गंभीरता से लिया और

वे डॉ. योगेश पंडग्रे को पंडग्रे की मांग को अमलीजामा पहनाने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए 660 मेगावाट की नई इकाई सतपुड़ा सारणी थर्मल पावर सेंटर के लिए स्वीकृति दे दी। बता दें कि 660 मेगावाट की बिजली इकाई की स्थापना को लेकर मिली स्वीकृति से सारणी पाथाखेड़ा क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। वहीं मिली जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. योगेश पंडग्रे को मुताबिक क्षेत्रवासियों की खुशियां उस समय और दोगुनी हो गई जब उन्हें यह जानकारी मिली कि क्षेत्र के विधायक डॉ. पंडग्रे के प्रयास से ही क्षेत्र में एक बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री भी स्थापित होने जा रही है, जिससे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

जिले में सबसे अधिक राशि आमला को– खबर को अगर सही माने तो बैतूल जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक डेवलपमेंट के लिए राशि आमला विधानसभा क्षेत्र के लिए 57 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है। जो कि निश्चित ही इसका श्रेय डॉ. योगेश पंडग्रे के कार्य प्रणाली को मिलना है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस समय बैतूल जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्र के

46 करोड़ 36 लाख से होगा सड़कों और पुल का निर्माण

घोड़ाडोंगरी विधायक के प्रयासों से अनुरूपक बजट में मिली स्वीकृति

बैतूल। घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा बाई उर्के के अथक प्रयासों से घोड़ाडोंगरी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 सड़कों और 2 पुल निर्माण को अनुरूपक बजट में मिली स्वीकृति है। विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में 46 करोड़ 36 लाख 65 हजार की लागत से स्वीकृत सड़क और पुल निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, वहीं स्थानीय निवासियों को आवागमन में आने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे विधायक श्रीमती गंगाबाई उर्के की बड़ी सफलता बताया। ग्रामीणों ने कहा कि यह स्वीकृति गांवों को मुख्याधार से जोड़ने और विकास की नई राह खोलने में महत्वपूर्ण



भूमिका निभाएगी। जानकारी के अनुसार घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिखल्दा खुर्द शाहपुर से ग्राम पंचायत कुण्डो के ग्राम कुसमरी तवा घाट 3 किलोमीटर पहुंच मार्ग का 345.00 लाख की लागत से निर्माण किया

जाएगा। इसी प्रकार ग्राम गोपालपुर में दिनेश के घर से ग्राम इमलीखेड़ा 7 किलोमीटर मार्ग का 945.00 लाख, ग्राम चांदढाना से मलताजपुर 5 किलोमीटर मार्ग का 675.00 लाख, पीपलबारी बरजोरपुर 3 किलोमीटर 405.00 लाख, कोयलारी वीरगुवाडी 2.60 किलोमीटर मार्ग का 351.00 लाख, कछर कोयलारी 3 किलोमीटर मार्ग का 405.00लाख तथा ग्राम कैरिया डोलियाढना पाहर मेन रोड 3.20 किलोमीटर मार्ग का 432.00 लाख की लागत से निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ढोहरामउ से भीमपुरा में मोरन नदी पर 384.75 लाख एवं ग्राम 356.40 लाख की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा।

एक्ट ईव फाउंडेशन ने जिला जेल में भेंट

किया बुक शेलफ और सदसाहित्य

देवास। शहर की सामाजिक संस्था एक्ट ईव फाउंडेशन द्वारा अपने सामाजिक प्रकल्पों की कड़ी में आज जिला जेल में मांग पर कैदियों के लिए बुक शेलफ और सदसाहित्य भेंट किया। छोटे किन्तु गरिमामयी कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्रीमती हिमानी मनवारे ने संस्था अध्यक्ष मोहन वर्मा का स्वागत किया वहीं एक्ट ईव फाउंडेशन की और से प्रवीण शर्मा ने श्रीमती हिमानी मनवारे और जेलर अनिल दुबे का स्वागत किया।बुक शेलफ और सदसाहित्य भेंट के इस अवसर पर मोहन वर्मा ने कहा- अच्छ मित्र और अच्छ साहित्य हमें विपरित परिस्थिति में भी सोचने सम्झने का अवसर देता है। कई बार क्षण भर का आवेश हमारी जिंदगी की दिशा और दशा ही बदल देता है। जिस तरह हम वाहन चलाते समय दिमाग के साथ बलच, गियर,ब्रेक का इस्तेमाल कर सुरक्षित वाहन चलाते है इसी तरह परिस्थिति जन्य



स्थितियों में भी संतुलन जरूरी है,ऐसे में अच्छी किताबें हमारी मदद करती हैं। जेल अधीक्षक श्रीमती हिमानी मनवारे ने इस अवसर पर कहा कि हमारा प्रयास यही रहता है कि यहीं रहकर लोग अपने समय को सकारात्मक चीजों से जोड़े रखें और इसी कड़ी में हमने अच्छी किताबों के साथ एक लायब्रेरी की स्थापना की कोशिश की है जिसका लाभ बंदी ले सकेगे।हम एक्ट ईव फाउंडेशन और मोहन वर्मा जी के आभारी हैं कि हमारे आग्रह पर संस्था द्वारा ये सीमागत दी गई।

भिक्षावृत्ति रोकने के लिए,एक जनवरी से भिक्षुक को भिक्षा देने पर संबंधित पर भी होगी एफआईआर

मोहन वर्मा, देवास । कहते है दया ही दुःख का कारण है। अपवादों को छोड़ दें तो जिन्हें गरीब लाचार समझकर लोग भीख दे रहे है वे लोगों की भावनाओं से खेल रहे है। कई बार भीख देने से इंकार करने पर मांगने वाला हमें गाली देकर जलील करने से भी नहीं चूकता।भीख देने के बदले यदि मांगने वाले को हम चाय, खाना या कुछ खिलाने की बात करते है तो वो इन्कार करके सिर्फ और सिर्फ नगद राशि की ही मांग करता है। उन्हें काम देने की बात करने पर वे कभी काटकर चलते बने होते हैं।

इंदौर में बीते दिनों भिखारियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में पुलिस के हाथों एक ऐसाव्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास 75 हजार नगद पाया गया। मुंबई में भीख माँगरक 70-80 हजार प्रतिमाह कमाने वाले के पास 1.5 करोड़ के फ्लैट के साथ बड़ी मात्रा में नगद राशि भी मिली है।

पूर्व में भी इंदौर में भिक्षावृत्ति के खिलाफ आदेश जारी किए जा चुके हैं अब



जाएगा। देश के सभी हिस्सों के साथ खासकर धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को भिखारियों द्वारा परेशान किए जाने के किस्से भी नये नहीं हैं।अगर उज्जैन की बात करें तो मंदिरों से लेकर अन्य धार्मिक स्थल के

अलावा स्थिति यह हो गई है कि लोग चाय, नाश्ता ज्यूस आदि प्लाईट पर भी खड़े नहीं हो पा रहे वहां भी भिक्षावृत्ति वाले चैन से खाने पीने भी नहीं देते इस प्रकार से उज्जैन में और ज्यादा यह समस्या बढ़ती जा रही है। जिस पर इंदौर में पाबंदी के बाद जैसा कि पहले भी सज्ञान में आ चुका है कि इंदौर से भिक्षुक पाबंदी बढने के बाद बस ट्रेन अन्य माध्यम से उज्जैन पहुंचकर भिक्षा मांग कर रात में ही इंदौर लौट जाते थे अब पुनः यहीं स्थिति बनेगी उज्जैन में इस समस्या की सख्ती से कदम उठाने की जरूरत क्योंकि बाहर से आ रहे पयंटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में इस प्रकार के आदेश निकलने के पीछे प्रशासन की मजबूरी यह है कि वहां पर चेकिंग के दौरान डेढ़ लाख रुपए महीने तक की इनकम भिक्षावृत्ति से निकली है वहीं इन लोगों के खुद के घर के मकान तक है फिर भी भीख मांग कर गुजारा करना आदत बन गई है। खबर है कि उज्जैन की बात करें तो बड़े-बड़े धार्मिक स्थलों के

आसपास भिक्षुकों की गैंग सक्रीय है और इलाके तक बांधे हुए हैं कि यहां पर अगर भिक्षा मांगनी है तो इसका इतना प्रतिशत हमें देना पड़ेगा तभी यहां पर बैठ सकते हो या घूम कर भीख मांग सकते हो हद तो यह है कि इनमें से कई लोगों के ब्याज तक पर पैसे चल रहे हैं, इस हिसाब से इनके सरगना की कमाई का अंदाजा लगाया जा सकता है,,,। भिक्षा वृत्ति रोकने के लिए जनता को भी जागरूक होना जरूरी हो गया है ज्यादातर भिक्षुक छोटे बच्चों को आगे कर रहे हैं जो ट्रैफिक सिग्नल से लेकर मंदिरों के आसपास चाय नाश्ता पॉईंट आदि पर पहुंच कर भीख मांगते हैं या महिला को अशहाय जैसे वृद्धा अवस्था बीमार आदि स्थिति में हो उसे भिक्षा दिया जाना पुण्य का काम होता है हट्टे कट्टे कमा के खाने जैसे लोग भिक्षा मांग रहे हैं और यह बीमारी कि तरह फैलती जा रही है।

को बहुत कम राशि हाथ में आती है।

3257 ने कराया पंजीयन, आधे से भी कम ने बेची उपज – जिले में सोयाबीन खरीदी के लिए 14 केन्द्र बनाये गये थे। जिस पर सोयाबीन उपज बेचने के लिए कुल 3257 किसानों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 1027 किसानों ने स्लॉट भी बुक कराया, लेकिन 2431 किसान ऐसे है, जिन्होंने उपज नहीं बेची। खरीदी केन्द्र पर मात्र 826 किसान उपज लेकर पहुंचे, जिनसे 2758.55 मैट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी गई। इशर मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में सोयाबीन बिकने आ रही है। यहां किसानों को समर्थन मूल्य की अपेक्षा कम भाव मिल रहे है, लेकिन फिर भी किसान मंडी में उपज बेचने के लिए पहुंच रहे है। इसके पीछे किसानों का मानना है कि समर्थन मूल्य में सोयाबीन खरीदी के जो मापदंड है, वह काफी कड़े है। जिससे किसानों केवल परेशानियां ही उठनी पड़ती है। इस वजह से किसान मंडी में सोयाबीन बेच रहे है।

किसानों को अब तक 8.51 करोड़ का भुगतान – कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन किसानों ने सोयाबीन बेची है, उन्हें कुल 13.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था, जिसमें

से 8.51 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। शेष 4.98 करोड़ रुपये के भुगतान की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। जल्द ही बचे हुए किसानों का भुगतान हो जायेगा। कृषि विभाग का कहना है कि खरीदी के बाद भुगतान की प्रक्रिया को 8 से 10 दिन का समय लगता है। चूँकि भुगतान किसानों के खाते में होता है। ऐसे में कई बार खातों की समस्या सहित अन्य कारणों से भुगतान में देरी होती है। तकनीकी कारणों से भी भुगतान जल्द नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द किसानों को भुगतान किया जा सके।

इनका कहना है –जब पंजीयन चल रहे थे, तब मंडी के भाव 4600 के आसपास चल रहे थे। इसलिए कई किसानों ने पंजीयन नहीं कराया। अक्टूबर में बारिश से सोयाबीन भी भीग गया था। जिससे सोयाबीन एफएक्यू स्टैंडर से कम हो गया। एफएक्यू के मापदंड के अनुसार सोयाबीन नहीं होने के कारण मंडी जा रही है। जिन किसानों ने उपज बेची है, उन्हें 8.51 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। बचे हुए किसानों को भी जल्द भुगतान हो जायेगा।

- आनंद बड़ोनिया, उपसंचालक, कृषि विभाग बैतूल



पुलिस विभाग ने स्कूली बच्चों को दी साइबर क्राइम की जानकारी

बैतूल। माईड्स आई इंटरनेशनल स्कूल, विनोबा नगर में 18 दिसंबर बुधवार को पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टीआई अरविंद कुमार, अनिरुद्ध यादव और एसडीओपी शालिनी परते मौजूद रहे। स्कूल संचालक अनिल राठौर और स्कूल सचिव डॉ. रिशांक राठौर ने भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की।

कार्यक्रम में अनिरुद्ध यादव ने साइबर क्राइम पर अपने विचार रखते हुए बच्चों को बताया कि किसी भी अपरिचित कॉल का जवाब न दें और हमेशा सतर्क रहें। उन्होंने बच्चों को चार्ल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी। टीआई अरविंद कुमार ने ट्रैफिक नियमों और नशा मुक्ति के विषय पर बात करते हुए हेलमेट के उपयोग और सुरक्षित ड्राइविंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों

●एसडीओपी शालिनी परते ने बच्चों को किया जागरूक

●टीआई अरविंद कुमार ने बताया हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का महत्व

●स्कूल संचालक अनिल राठौर और सचिव रिशांक राठौर ने दिया बच्चों को प्रेरक संदेश

●माईड्स आई इंटरनेशनल स्कूल में चलाया जागरूकता अभियान

●साइबर क्राइम, ट्रैफिक नियम और पॉक्सो एक्ट पर हुई चर्चा



का पालन करना कानून का सम्मान है, यह खुद की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। एसडीओपी शालिनी परते ने बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में विस्तार से समझाया और पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को सतर्क रहने और किसी भी असामान्य स्थिति में तुरंत अपने परिजनों या शिक्षकों को बताने की सलाह दी। स्कूल सचिव डॉ. रिशांक राठौर ने बच्चों को लालच और प्रलोभन से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपरिचित कॉल्स से दूरी बनाए रखना और सतर्क रहना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्राचार्या रश्मि कमाविसदार ने सभी अतिथियों और उपस्थितजनों का धन्यवाद किया। इस मौके पर स्कूल के सभी छात्र-छात्राएं और स्टाफ मौजूद रहा।

चूल्हा जलाते समय आग लगने से झुलसी महिला, भोपाल रेफर

बैतूल। चूल्हा जलाते समय एक महिला आग लगने से बुरी तरह झुलस गई। हादसा चूल्हे के पास रखी डीजल की बोतल गिरने से हुआ। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बैतूल के मिलनपुर गांव का है। जानकारी के अनुसार सोनम पति मनीष धुवू (27) किला खंडारा की रहने वाली है। सोनम बुधवार को खाना बनाने के लिए डीजल का चूल्हा जला रही थी। वह चूल्हा जलाने के लिए कैरोसिन की जगह भिंडी का इस्तेमाल कर रही थी। इसी दौरान चूल्हे के पास रखी डीजल की बोतल को धक्का लगा गया। जिससे डीजल महिला और चूल्हे के ऊपर गिर गया। डीजल गिरने से अचानक आग भड़क गई और महिला आग की चपेट में आ गई। इस पूरी घटना में महिला गले से कमर तक 40 प्रतिशत झुलस गई है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल (म.प्र.)									
// निविदा आमंत्रण सूचना //									
निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का शिथिल शिथिल वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। मध्यप्रदेश भग्नाह्न काय नियम के धिन्दू क. 10 (निविदाओं के संबंध में) अर्न्तगत 10.1.3 सामान्य: निविदा के रहल अस्पकारिक निविदा आमंत्रित करने हेतु सरल क्रमांक (iii) के अनुसार 07 दिवस की निविदा जारी की जाएगी।									
क्र.	टेंडर नम्बर	जि़ला	कार्य का प्रकार	लघु निर्माण कार्य / मरम्मत	अवन्नम कम्पाक	कार्य की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानित राशि	समय अवधि	नोटिड रूप से एक्लस प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफडीआर एवं इस्तक़ीद)
1	2024 MPP-388276_1	बैतूल	नवीन चौकी निर्माण कार्य	पुलिस चौकी सोनघाटी थाना कोयलारी में नवीन कक्ष का निर्माण कार्य (लघु निर्माण कार्य)	प्रथम आमंत्रण	2,97,000/-	5,000/-	45 दिवस	EMD and all documents Submission Online Only
2	2024 MPP-388240_1	बैतूल	मरम्मत कार्य	पुरान थाना सोनपुर पुलिस म्युडियम मरम्मत कार्य (बिजली त्रिपिंग, प्लास्टर व फ़्लोइडिंग शीट)	प्रथम आमंत्रण	5,00,000/-	10,000/-	21 दिवस	--do--
3	2024 MPP-388262_1	बैतूल	मरम्मत कार्य	पुरान थाना साईडेल का मरम्मत कार्य (बिजली त्रिपिंग, प्लास्टर एवं फ़्लोइडिंग शीट)	प्रथम आमंत्रण	5,00,000/-	10,000/-	21 दिवस	--do--
4	2024 MPP-388233_1	बैतूल	नवीन कक्ष निर्माण कार्य	जन शिविरगत निवारण कक्ष निर्माण कार्य पुलिस कार्यालय परिसर बैतूल	प्रथम आमंत्रण	5,00,000/-	10,000/-	45 दिवस	--do--

संपर्कित वेबसाइट पर अधिकतम भुगतान करने के अवसर पर निविदा प्रार (टेंडर क्लरिफिक) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्राप्त कराने की अंतिम तिथिंक 19/12/2024 सांठ 3.30 बजे स्थिति है। निम्न पुनःआर्डी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले क़ायम कोर्रिन्स का प्रक़रन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किता ज़रूरी है। पुनः से जानकारी एवं में प्रक़रन नही किता ज़रूरी है। म.प्र. भग्नाह्न काय नियम क़ायम क़ायम ज़रूरी निविदा 20/15 (काय संपर्कित 2022) में दिने नये निविदा एवं नई निविदादुनर क़ायम होगी।

पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल

मनीष बागवानी बने भाजपा संतनगर मंडल अध्यक्ष

● सिंधी समाज ने शॉल श्रीफल देकर किया अभिनंदन, वरिष्ठ जनों ने दी बधाई



भोपाल । भाजपा संत नगर मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में मनीष बागवानी की नियुक्ति से सिंधी समाज में खुशी की लहर है। उनकी नियुक्ति पर समाज और भाजपा संत नगर द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रमुख समाजसेवियों और भाजपा नेताओं ने भाग लिया।समारोह के दौरान मनीष बागवानी का स्वागत शॉल और श्रीफल से किया गया। समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने बागवानी की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। अभिनंदन करने वालों में प्रमुख रूप से राजेश बेलानी, मोहन लालवानी, पंचायत अध्यक्ष माधु चांदवानी, हरीश केसवानी, बसंत चेलानी, गुलाब जेटानी, कमल विधानी, कन्हैया इसरानी, पंडित जयकुमार शर्मा, राजू वर्मा, प्रदीप बसरेजा, सोनू रायचंदानी, वासुदेव झमतानी, शेड्डी चंदनानी, नवीन मनसुखानी आदि शामिल रहे।

5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी

● 24 फरवरी से शुरू होगी

भोपाल (नप्र) । मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 5 और 8 के लिए साल 2025 की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। आधिकारिक टाइम टेबल के अनुसार, पांचवीं कक्षा की परीक्षाएं 1 मार्च 2025 को खत्म हो जाएंगी। जबकि आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 5 मार्च 2025 तक चलेंगी। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं पहली भाषा के पेपर (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी) से शुरू होंगी। पांचवीं की परीक्षा दूसरी भाषा के पेपर के साथ समाप्त होगी, जबकि आठवीं की परीक्षा तीसरी भाषा के पेपर के साथ आयोजित होगा।

पति से अफेयर के शक में महिला की हत्या

● जबलपुर में महिला ने किया चाकू से हमला पति को रंगे हाथ पकड़ने गई थी

जबलपुर । जबलपुर में पति से अफेयर के शक में पत्नी ने एक महिला की हत्या कर दी। शहर की प्रोफेसर कॉलोनी में महिला ने दो महिलाओं पर चाकू से हमला किया। गर्दन पर हुए वार के चलते एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना माढ़ोताल थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक शिखा नाम की महिला को शक था कि उसके पति का पड़ोस में ही रहने वाली महिला से अफेयर चल रहा है। इसी संदेह के चलते वो पति को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उस महिला की सहेली के घर पहुंची थी। यहीं उसने चाकू से हमला किया।

बीच-बचाव करने आई सहेली पर भी हमला

बुधवार दोपहर को शिखा को पता चला कि पति की प्रेमिका अपनी सहेली के घर आई हुई है। वो यहीं पर वो उसके पति से मिलने वाली है। थोड़ी देर में शिखा उसके घर पहुंची, जहां पर वो महिला बैठी थी, जिस पर उसे शक था। दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान शिखा ने पास ही रखा चाकू उठाया और उसके पेट में मार दिया। चाकू लगते ही पेट से खून बहने लगा। बीच-बचाव करने आई सहेली पर भी शिखा ने चाकू से हमला कर दिया।

एक की रास्ते में मौत, एक की हालत गंभीर – वारदात को अंजाम देने के बाद शिखा मौके से फरार हो गई है। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया। एक को हालत गंभीर होने के चलते उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं, मृतका की सहेली की हालत नाजुक बनी हुई है। युवती की हत्या करने वाली महिला वारदात के बाद मौके से फरार हो गई। जानकारी लगते ही माढ़ोताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी विपिन तासकार ने बताया-शिखा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर, उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि शक के संदेह पर हत्या की गई है।

एम्स शोधार्थियों का एपीपीआईकॉन राष्ट्रीय सम्मेलन में शानदार प्रदर्शन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, संस्थान ने एक बार फिर चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को साबित किया है। एम्स भोपाल के पीएचडी छात्रों ने चेन्नई में आयोजित एपीपीआईकॉन 2024 (एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट्स एंड फार्माकोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया सम्मेलन) में अपने शोध प्रस्तुत किए। सम्मेलन में प्रस्तुत शोधों में प्रमुख रब डॉ. राहुल गौर का अध्ययन, जिसमें रिपिटिटिव ट्रांसक्रैनिअल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के जरिए क्रॉनिक लो बैक पेन के प्रबंधन के लिए एक नवीन, गैर-आक्रामक चिकित्सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। डॉ. संतोष वाकोडे, डॉ. वरुण मल्होत्रा, और डॉ. सोफिया मुद्दा के मार्गदर्शन में किए गए इस केस स्टडी ने पीढ़ा में उल्लेखनीय कमी, हृदय गति परिवर्तनशीलता में सुधार, और रोगियों में बेहतर संज्ञानात्मक प्रदर्शन (पी 300 लेटेसी में कमी) प्रदर्शित किया। यह शोध एम्स भोपाल में स्थापित उन्नत आरटीएमएस लैब और संस्थान के अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। एक अन्य प्रस्तुति तनुशा पाठक द्वारा दी गई, जिसमें पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) फेनोटाइप्स में नींद, चिंता और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। डॉ. सोफिया मुद्दा और डॉ. संतोष वाकोडे के मार्गदर्शन में किए गए इस अध्ययन ने विभिन्न पीसीओएस फेनोटाइप्स के बीच मनोवैज्ञानिक और जीवन गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर उजागर किए। गंभीर फेनोटाइप (ए और बी) में कमजोर परिणाम पाए गए, जबकि फेनोटाइप डी में सबसे बेहतर परिणाम देखे गए। यह शोध फेनोटाइप-विशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता और पीसीओएस उपचार में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के समावेश को रेखांकित करता है। इस सम्मलेन के महत्व पर प्रो. सिंह ने कहा, यह एम्स भोपाल के लिए गर्व का क्षण है।

गृह मंत्री शाह के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलता जलाया

● संविधान से देश चलता है, अमित शाह देश की जनता से माफी मांगे, भाजपा का चरित्र हुआ उजागर

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के समीप कांग्रेसजनों ने बाबा साहेब अमर रहें के नारे लगाकर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करने और उनकी आलोचना करने के विरोध में देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुलता दहन कर विरोध प्रदर्शन किया।

श्री अहिरवार ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे अमित शाह ने जिस तरह लोकसभा में सार्वजनिक तौर पर अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस संविधान की शपथ लेकर अमित शाह देश के गृह मंत्री बनकर बैठे हैं, उसी संविधान निर्माता का अपमान केंद्र की मोदी सरकार और उसमें बैठे मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा किया जाना उनका चाल, चरित्र और चेहरा उजागर

करती है। अमित शाह की सोच और मानसिकता दिवालिया हो चुकी है, उन्हें किसी अच्छे सर्जन से अपना मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। जब देश का गृह मंत्री ही संविधान निर्माता बाबा साहेब का अपमान करे तो देश की कानून व्यवस्था कैसी चलेगी, यह देश की जनता समझ सकती है?

श्री अहिरवार ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को संविधान में प्रदत्त अधिकार दिये, वे सर्वहारा वर्ग के मसीहा हैं। देश की जनता को समतामूलक, समावेशी भावना को दृष्टिगत रखते हुये



स्वतंत्रता से जीने के मौलिक अधिकार दिये, उसी की परिणिाति है कि आजादी के बाद आज तक हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश संविधान से चलता है। अमित शाह ने लोकसभा में जिस प्रकार से बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है, देश की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार को अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा लेना चाहिए।

श्री अहिरवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमित शाह ने देश की जनता से माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग को पूरा अजा वर्ग अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, उग्र आंदोलन कर मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक कूच करने के लिए विवश होगा।

विरोध प्रदर्शन के दौरान मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, पूर्व राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल, भूपेन्द्र गुप्ता, रवि सक्सेना, स्वदेशी शर्मा, अमित शर्मा, आनंद जाट, अभिनव बरोलिया, मिथुन अहिरवार, किशन अहिरवार, पवन पटेल, हेमंत नरवरीया, मुकेश बंसल, विनोद सूर्यवंशी, नीरज चंडाले, कुनाल गजभिये, टीआर गेहलोद, विकी कंडेर, शुभम इंद्रासे, दर्शन कोरी, जे.पी. रोहर, रामकन्हैया, विनोद बघेल, शुभम अहिरवार, विनय मालवीय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

रविन्द्र भवन भोपाल में ‘डकिया डाक लाया’ 22 को

मुंबई के विक्रम जीत के निर्दर्शन में संगीतमय शाम

भोपाल । महेश मेलेडी मूवमेंट (एम-श्री) ग्रुप 22 दिसंबर (रविवार) को रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में ‘डकिया डाक लाया’ संगीतमयी आयोजन करने जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। ग्रुप के अध्यक्ष दिनेश गर्ग और वॉइस ऑफ किशोर

निर्देशन में की जाएगी।

क्लासिकल संगीत के इस आयोजन में की-बोर्ड पर दिवाकर परख (मुंबई), मुकुल शर्मा (ग्वालियर), लक्षित अय्यर (भोपाल), वायलिन पर रईस शाह (मुंबई), सेक्सोफोन पर मनीषा यादव (इंदौर), तुम्बा पर आकाश



अरविंद दयाल शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक आमंत्रण पत्र के साथ एक व्यक्ति का नि:शुल्क प्रवेश होगा। कार्यक्रम की एंकरिंग प्रसिद्ध सिंघार और वॉइस ऑफ रफ़ी, अशोक सिंह द्वारा की जाएगी। वहीं, साउंड निबंधन का कार्य मनोज खरे सभालगे और संगीत संयोजन की जिम्मेदारी मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार विक्रम जीत सिंह ‘विकी’ के

अग्रवाल, जोनोद शर्मा, सुशील कैथल, लक्षित अय्यर सहित फीमेल सिंगर्स मनीषा यादव, अमोषी मालवीय, माहुरि शर्मा, प्रतिमा गोस्वामी, अनन्या कुलश्रेष्ठ, वंदना सोनी, अंशिका राजौरिया, सर्वेस राजा, मीता दास, पररहत खान, रिकी सोनकर, रिया रसालिका अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरेंगे।

आईटी पार्क का सीएम करेंगे भूमिपूजन

अधिकारी साइट विजिट करने पहुंचे; हर फ्लोर पर होगी हाइटेक सुविधाएं

उज्जैन । उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 दिसंबर को आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे। प्रथम चरण में 46 करोड़ रुपए की लागत से आईटी पार्क निर्मित होगा। आईटी पार्क

फेज में आईटी पार्क का निर्माण होगा -राजेश राठौर ने बताया कि उज्जैन शहर के लिए आईटी पार्क की सौगात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईटी पार्क बनने से छात्रों को बेहतरीन उच्च गुणवत्ता

के बनने से कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस उज्जैन में खुल सकेंगे। जिससे उज्जैन में आईटी से जुड़े छात्रों शहर से बाहर नहीं जाना होगा।उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह, एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश राठौर, जिला पंचायत सीओ जयती सिंह, एडीएम अनुकूल जैन, निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनने वाले आईटी पार्क की जमीन को देखने के लिए पहुंचे। सीएम मोहन यादव यहीं पर शनिवार को आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इसके लिए साइट को क्लियर करवाने का काम शुरू हो चुका है। एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश राठौर ने बताया-कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल पर स्थित सभा कक्ष में आईटी पार्क के भूमि पूजन की तैयारियों के संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।दो



की शिक्षा प्राप्त होगी और उज्जैन शहर के लिए औद्योगिक विकास को भी निरंतर वृद्धि होगी। उज्जैन में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। आईटी पार्क शुरू होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था में बूम आएगा।आर्वाटिक्ट भूमि में दो फेज में पार्क का निर्माण होगा। प्रथम चरण में लगभग 5400 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा।

जिससे लगभग 1.2 लाख वर्ग फुट आवांटेन योग्य आईटी स्पेस का निर्माण किया जाएगा। लगभग 30 आईटी इंडस्ट्री अपना प्लग एंड प्ले आधारित मॉडल पर कार्य प्रारंभ कर सकेंगी।

उज्जैन में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए दो साल की डेडलाइन आते की गई है।**ऐसा होगा उज्जैन का आईटी पार्क** –एमपीआईडीसी के राजेश राठौर ने बताया कि हम इस आईटी पार्क में टेक कंपनियों और स्टार्टअप को सभी तरह की एडवांस सुविधाएं देंगे। यह उज्जैन का अपने आप में पहला पार्क होगा। सरकार का इस बात पर जोर है कि स्थानीय युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाए। आईटी पार्क से उज्जैन में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आईटी पार्क 2.161 हेक्टर जमीन पर बनेगा। इसमें 11239 स्केयर मीटर में बिल्डिंग बनेंगी, बिल्डिंग की ऊंचाई 31.7 मीटर होगी। जिसमें हर फ्लोर पर टॉयलेट के साथ कैफेटेरिया ड्रिंकिंग वाटर, लिफ्ट के साथ ऑफिस के लिए हाइटेक सुविधा भी मिल सकेंगी। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर 59 कार पार्क हो सकेंगी।

श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेन सुल्तानपुर तक जाएंगी, 24 दिसंबर से बदलेगा रूट

जबलपुर। जबलपुर होकर अयोध्या केंट तक संचालित होने वाली तीन साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 24 दिसंबर से 7 जनवरी के मध्य सुल्तानपुर तक जाएंगी। ये तीनों ट्रेन, एलटीटी-अयोध्या केंट (22183/84),



एलटीटी-अयोध्या केंट-एलटीटी (22103/04) और रामेश्वरम-अयोध्या केंट-रामेश्वरम श्रद्धा सेतु (22613/14) एक्सप्रेस है।संबंधित अवधी में एलटीटी-अयोध्या-एलटीटी (22103/04) और श्रद्धा सेतु (22613/14) एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर जफराबाद-जौनपुर सिटी (परिवर्तित मार्ग) होकर चलेंगी। उक्त ट्रेनों संचालन भी अयोध्या

केंट के स्थान पर सुल्तानपुर स्टेशन से आरंभ होगा। यह निर्णय अयोध्या केंट स्टेशन में यार्ड रिमाडिंग कार्य के कारण किया गया है। इस दौरान उक्त रेलवे लखनऊ मंडल के बाराबंकी-अयोध्या केंट-जफराबाद रेलखंड पर अधोसंरचना निर्माण कार्य होना है। इसके कारण भी कुछ अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। दुर्ग- नौतनवां 18205 एक्सप्रेस 19, 26 दिसंबर व दो जनवरी और नौतनवां-दुर्ग 18206 एक्सप्रेस 21, 28, दिसंबर एवं चार जनवरी को दोनों दिशाओं में अपने पूर्व मार्ग के स्थान पर मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-वाराणसी-जौनपुर-ओरिहार होकर जाएंगी।

गोरखपुर-यशवंतपुर 15023 एक्सप्रेस 24, 31 दिसंबर एवं सात जनवरी और यशवंतपुर-गोरखपुर 15024 एक्सप्रेस 19, 26, दिसंबर एवं दो जनवरी को अपने पूर्व मार्ग के बजाय गोरखपुर-गोंड-बाराबंकी होकर संचालित होगी। इस दौरान छपरा-एलएलटी-छपरा एक्सप्रेस (15101/02) छपरा-गोरखपुर-गोंड-बाराबंकी-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल होकर चलेंगी।

मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में लापरवाही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निलंबित

भोपाल जिप सीईओ गांवों में पहुंचे; महिलाओं से पूछा- लाभ मिल रहा या नहीं?



भोपाल । मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व में लापरवाही बरतने पर भोपाल जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह ने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया। बुधवार को वे गांवों में पहुंचे थे। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं? पर्व के तहत 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में शिविर

लगाए जा रहे हैं। बुधवार को भी शिविर लगाए गए। इनमें सीईओ ऋतुराज भी शामिल हुए। उन्होंने ग्राम पंचायत फंदाकलां, ईटरखेड़ी छाप और बरखेड़ा नाथू पहुंचकर हितग्राहियों से चर्चा की। योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। जनपद फंदा सीईओ शंकर पांसे, एपीओ संदीप कुमार श्रीवास्तव भी साथ थे।

अधिकारी-कर्मचारी शिविर में

लहसुन की तस्करी पर रोक नहीं लगा रही सरकार

● किसानों में भारी आक्रोश : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इंदौर के चौधराम मंडी पहुंचकर किसानों के साथ चीन के लहसुन विरोध में किसानों की आवाज उठाते हुये अपने एक वक्तव्य में चीन से अफगानिस्तान के रास्ते आने वाले भारी मात्रा में लहसुन पर रोक न लगाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम मध्य प्रदेश में किसान सड़कों पर उत्तकर आंदोलन कर रहे हैं। श्री पटवारी ने कहा है 2014 में भारत सरकार ने चाइनीस लहसुन को अमानत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताकर प्रतिबंधित किया है। ऐसी स्थिति में हजारों टन लहसुन का आना मध्य प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इस लहसुन के बारे में कहा गया है कि यह पेट में अल्सर और अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस लहसुन को बेचे जाने पर रोक लगाकर फटकार लगाई थी और सख्त टिप्पणी की थी। श्री पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में खासतौर से पश्चिम मध्य प्रदेश में किसान बहुत बड़े मात्रा में लहसुन की खेती करता है। चीन का लहसुन आने से लहसुन के दाम 50 प्रतिशत तक गिर गए, जिसके कारण मध्य प्रदेश के किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। जिसके विरोध में हजारों किसान सड़क पर उत्तरकर आंदोलन कर रहे हैं। सब्जी मंडी पहुंचे श्री पटवारी जी ने किसानों को संबोधित करते हुये कहा कि किसानों द्वारा किये जा रहे इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन को सरकार अनदेखा कर रही है और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही। एक तरफ तो सरकार किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, दूसरी तरफ चीन से होने वाली लहसुन की तस्करी पर रोक भी नहीं लग पा रही है, जिससे किसानों में भारी निराशा है। श्री जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों की एक-एक लड़ाई को कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी और इस किसान विरोधी प्रदेश को भाजपा सरकार को किसी भी कीमत पर बेलगाम नहीं होने देगी। चाइना लहसुन का विरोध कर रहे किसानों की आवाज तराना के जुझारू विधायक महेश परमार जी के जरिए विधानसभा तक पहुंचाई गई।

एम्स भोपाल द्वारा चिकलोद कला गांव में

योग स्वास्थ्य और मेटेरियोविजिलेंस पर जागरूकता अभियान का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में आयुष विभाग, फार्माकोलॉजी विभाग और सामुदायिक एवं परिवारिक चिकित्सा विभाग के सहयोग से चिकलोद कला गांव के



प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र में योग, स्वास्थ्य और मेटेरियोविजिलेंस पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस आयोजन में दो मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल थे: आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग और स्वास्थ्य शिविर, और फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा मेटेरियोविजिलेंस जागरूकता अभियान का उद्देश्य समुदाय को चिकित्सा उपकरणों और उपचारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता के

बारे में ग्रामीणों को जानकारी देना था।

प्रो. सिंह ने इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों का हिस्सा है। योग और मेटेरियोविजिलेंस के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल उन्हें अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सचेत करता है, बल्कि उन्हें बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है।

कार्यक्रम में आयुष विभाग द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों और ग्रामीणों को योग सिखाया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लाभ के बारे में जागरूक करना था। शिविर में स्वच्छता, संतुलित आहार, और नियमित व्यायाम के महत्व पर भी चर्चा की गई। इस सत्र में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योगसन तथा प्राणायाम सीखा। इसके साथ ही, फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित मेटेरियोविजिलेंस जागरूकता अभियान का उद्देश्य समुदाय को चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और प्रभावशीलता की निगरानी के महत्व के बारे में जानकारी देना था।

